Preparation of New Curriculum by NCERT

*668. SHRI EDUARDO FALEIRO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) Whether NCERT has been asked to prepare a new national curriculum framework for schools;

(b) if so, the directions that have been given to NCERT in preparing the new curriculum framework; and

(c) whether the new curriculum would be placed before the Central Advisory Board of Education (CABE) for apaproval, before it is finalised?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The National Policy on Education—1986 [as updated in 1992] and Programme of Action—1992 stipulate that there should be curriculum renewal before the end of the 8th Five year Plan period. In pursuance of the same and similar recommendations of the Ninth Plan document in this regard, NCERT [an autonomous organisation of Department of Education] has prepared a "Discussion Document' on National Curriculum Framework for School Education. Previously, NCERT had brought out the ""National Curriculum for Elementary and Secondary Education, A Framework' in 1988.

(b) No directions have been given to NCERT for preparing the discussion Document.

(c) After due deliberations across the country, as soon as NCERT finalises the document, it shall be palced before the Central Government for approval, after a formal consultation with the State Governments.

SHRI EDUARDO FALEIRO: I would like to know why the new curriculum has not been placed before the Central Advisory Board of Education, that is, CABC. I think this is really a forum where a discussion can take place, rather than dealing with it on one-to-one basis with the States. When we are having a conference of all the State Education Ministers here, I think it is the best way fo dealing with an issue which is of national educational significance. It is a crucial issue and is of national educational significance.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The NCERT has prepared a document of discussion and they are discussing it with various broads and agencies.

When they finalise the document and come before the Government, we will certainly take it into consideration.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, part (b) of my question is this. At what stage is the discussion on? Will the hon-Minister also place this very important document before Parliament for a discussion?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: This document is rearding the updating of curriculum, and, to the best of my knowledge, updating of curriculum has never been placed before Parliament. But if the hon. Member wants to discuss it, I would be very happy to discuss it in the House, but I think it has never been done before. Under the Education Policy, it is mandatory for the NCERT to update the curricula after every five years. This is their mandatory work which they are doing.

SHRI KULDIP NAYYAR: Is there any proposal to rewrite history, or, part of it?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: There is no proposal to rewrite anything. There is a proposal only to update the knowledge in all branches.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister has stated that discussion is going on. By which time he expect to have a response from the State Governments and when will it be finalised? Does he have any time-frame in his mind?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: We have to ask the NCERT to finalise this work by this July.

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जो भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन और सुधार होने की बात चल रही है, क्या अभी ऐसा कोई विचार है कि वे पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाए जाएं? क्योंकि जो स्थिति बनती जा रही है....केवल भारतीय भाषाएं विषय मात्र के रूप में पढ़ाई तो जाती हैं लेकिन विभिन्न विषयों को, जो अन्य सामाजिक विषय हैं जैसे भूगोल, विज्ञान, उन्हें भारतीय भाषाओं में सामान्यत: बड़े स्कूल नहीं पढ़ाते हैं। क्या यह स्थिति बनाई जा सकती है कि जो पाठ्क्रम तैयार किए जाए, उनमें से कुछ विषय सामाजिक विषय जो हों, वे भारतीय भाषाओं में अनिवार्यत: पढ़ाए जाएं?

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में यही पद्धति है। वहां पर अधिकांश सामाजिक ज्ञान के विषय हिन्दी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन: मेरा प्रश्न केन्द्रीय विद्यालय से संबंधित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में है।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: कृपया उत्तर सुन लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अतर्गत भारतीय भाषाओं में मातृभाषा में पठन-पाठन की नीति का अवलंबन है और सरकार नीति का अनुसरण करती है।

श्री नरेन्द्र मोहन: मान्यवर, जैसा मैंने कहा ऐसा हो नहीं रहा है। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा तो यह प्रश्न आवश्यक बन जाता है। सरकार इस पर कोई आवश्यक कदम नहीं उठाती। आज के दिन अधिकांश स्कूलों में....

श्री सभापति: साफ हो गया है।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। केन्द्रीय सरकार बराबर राज्य सरकारों से संपर्क रखती है और अनुरोध करती रहती है कि वे इस नीति का अवलंबन करें, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है और स्कूलों की शिक्षा राज्य सरकारों के द्वारा संचालित होती है। हमारा उनके बराबर यह अनुरोध रहता है कि शिक्षा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाए। इसके लिए पाठक्रम तैयार किए जाएं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महोदय, हमारे मंत्री जी इस बात से अवगत होंगे कि पिछले दिनों इनके मंत्रालय द्वारा देश की शिक्षा के आध्यात्मिककरण और देशीकरण को लेकर प्रश्न उठाया गया था, इससे पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश के कई विद्वानों ने प्रश्न उठाया था कि किस तरह से शिक्षा का सामाजिकरण किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि एनसीईआरटी की एक कमेटी ने हमारे कुछ प्रदेशों विशेषकर मध्य प्रदेश और गुजरात की पुस्तकों का अध्ययन किया। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया कि उन पुस्तकों में हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया है और छात्रों के दिमाग में जहर घोला गया है। अगर मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है तो इन्होंने क्या रुख अख्तियार किया है और इस पर कोई एक्शन लिया या नहीं लिया है?

इसके साथ ही मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूं। हमारे मंत्री जी फिलहाल जो नया पाठ्यक्रम बनाने जा रहे हैं उसको लेकर तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के लोगों के बीच कोई शंका न उठे इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी पिछले दिनों जो तमाम शंकाएं उठी थीं उनका निराकरण करेंगे और इस बात का यहां आश्वासन देंगे कि शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा तथा हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बहाल किया जाएगा?

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: इस देश की शिक्षा के साथ न कोई खिलवाड़ हो रहा है और जब तक मैं मंत्री हूं न ही होने दिया जाएगा।

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं आपको गुजरात की किताबों का उदाहरण देती हूं, आप देख लीजिए। .....(**व्यवधान**).....गुजरात में अभी अत्याचार हुआ है। .....(**व्यवधान**).....

श्री सभापति: वे जवाब दे रहे हैं। आप उनको जवाब नहीं देने देती हैं। उनको जवाब देने का हक है और आपको सवाल करने का हक है। उनकी बात सुनिए

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, मैं तो बता रही हूं कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।....(**व्यवधान**)....

श्री एम. वेंकैयानायडु: आपने सवाल पूछा है तो मंत्री जी को जवाब भी देने दीजिए।....(**व्यवधान**).....

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: हमारा जो दायित्व है उसे हम पूरा करेंगे। हमने एनसीईआरटी की पुस्तकों में सुधार कर दिया है। जो गुजरात की पुस्तकें आज से नहीं बल्कि ये 1992 से चल रही हैं, इनके संबंध में जानकारी अब हमारे ध्यान में लाई गई। इसलिए हमने आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और हम ऐसे राज्यों से भी पुस्तकें मंगाने की चेष्टा कर रहे हैं जो हमारी घोषित राष्ट्रीय नीति के विपरीत है। पश्चिम बंगाल के बारे में भी कुछ इसी प्रकार की पुस्तकों का अभिज्ञान मिला है। हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। जहां तक शिक्षा के आध्यात्मिककरण का सवाल है, हमारी कमेटी की रिपोर्ट है कि वैल्यु एजुकेशन एक अभिन्न अंग है उससे पहले इस प्रकार की अनेक सिफारिशें मिली हैं कि शिक्षा मूल्य दृष्टि की होनी चाहिए, मानव मूल्यों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। हम शिक्षा में फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे संविधान की धारा अनुच्छेद 51-ए में वर्णित है उसको भी शामिल करना चाहते हैं। हम भारत द्वारा विश्व सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान में किए गए योगदान को भी अपने छात्रों को बताना चाहते हैं। मैं फिर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की शिक्षा नीति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा लेकिन कुछ सम्मानित सदस्यों और विद्वानों को वहां भेड़िया दिखाई दे रहा है जहां है नहीं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, ...(**व्यवधान**).....

श्री सभापति: श्री सी॰ रामचन्द्रैया। नो-नो, श्री रामचन्द्रैया, रामचन्द्रैया।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, whether the hon. Minister is aware that the quality of paper and colour schemes of the books that have been printed by the NCERT, especially the books that are meant for children, is very poor. I would like to know whether the hon. Minister can initiate some measures so that the quality of paper, as also the colour schemes of these books is improved.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, compromise with quality is being

done because of the subsidy given to the books. The idea behind this is, these books should be accessible to even those students whose purchasing power is low. Therefore, we cannot afford to give the best paper but, certainly, we will try to improve, within the limits.

†**श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक:** सभापति महोदय, हाल ही में एक स्कैण्डल पकड़ा गया है कि एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ की किताबों की नकल उतार कर लोग लाखों-करोड़ों किताबें बाजार में लाए हैं। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि कहीं इसमें एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ के कर्मचारियों का हाथ तो नहीं है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: ऐसी कोई शिकायत अभी तक हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है । यदि सम्मानीय सदस्य के पास ऐसी कोई सूचना आई है तो हम अवश्य उसकी जांच करेंगे।

*669. *[The questioner (Shri Bachani Lekhraj) was absent. For Answer Vide page 37 infra]*

Pollution in Yamuna River

*670. SHRI PREM CHAND GUPTA:
SHRI C.M. IBRAHIM:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Supreme Court has rapped the Delhi Government for not being able to control pollution in the Yamuna River;

(b) whether Comptroller and Auditor General's report for the year ending March, 1999, too has come down heavily on Government for haphazard handling of the problem;

(c) whether out of 2852 Million liters per day (MLD) sewage generation in the capital, only 866 MLD is treated and 1966 MLD of sewage is discharged into the river, causing serious pollution; and

(d) if so, what action Government are taking to resolve this problem?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) According to a study conducted by the Water and Power Consultancy

†Transliteration of the Speech in Persion Script is available in the Hindi version of the Debates.